हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 01 अंक : 350 : जौनपुर, गुरुवार 21 सितम्बर 2023 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य : 2 रूपया

मोदी की हैट्रिक खातिर अलर्ट हुआ संघ

एजेन्सी

लखनऊ। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर जिताकर लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस गुणा गणित फिट करने में लग गया है। परीक्षाफल सम्मानजनक आये तो एक्सट्रा क्लास तो शिक्षक को लेनी पड़ती है। संघ इसी भूमिका में है। बीजेपी के लिये यूपी में चुनावी पिच दुरूस्त करने खातिर ही लखनऊ में समन्वय मीटिंग हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया, इसको इलेक्शन में मुनाफेमन्द बनाने की तरकीब बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुझाई जा रही है। महिला आरक्षण बिल की मुखालफत तो खुलकर कोई दल नही कर रहा है, कुछ संशोधन के पक्षधर जरूर है। कोई पिछड़े वर्ग की बकालत कर रहा है तो कोई एससी एसटी के लिए भी आवाज उठा है। मायावती ने तो 50

फीसदी की बात कह अपने समर्थकों को लुभाया हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्व.मुलायम सिंह 13 वर्ष पहले इस मसले पर अपनी राय जुदा रखी थी। संघ और बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरने का मन बना चुके हैं। आधी आबादी पक्ष में खड़ी हो जाये तो बल्ले बल्ले तय है। उज्ज्वला योजना गृहणियों की खास पसन्द रही है।अब मोदी के संसद में 33 फीसदी आरक्षण के पेश बिल को मास्टर स्ट्रोक के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान है।लखनऊ में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक में दत्तात्रेय होसबाले और अरुण कुमार ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि भाजपा और सरकार संघ के अनुषांगिक संगठनों के साथ समन्वय और संपर्क बढ़ाएं। जमीनी फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्था को और दुरूस्त करें। आरएसएस को थिंक टैंक और संघ के पदाधिकारियों को थिंकर माना जाता है, वे पार्टी, सरकार और जनता के बीच रहकर सतत फीडबैक लेते और समीक्षा करते रहते हैं। संघ चाहता है कि संगठनों से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं का समाधान करें। अयोध्या के राममंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले विहिप 30 सिंतबर से 10 अक्तूबर तक शौर्य यात्रा निकालने जा रही है। शौर्य यात्रा को सफल बनाने के लिए सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार ने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं का अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने में यह बिल गेंम चेंजर बन सकता है बशर्ते इस बिल की बाबत आधी आबादी को समझाने में कोताही न हो जाये। महिलाओं को खुश करने के लिए अनुषांगिक संगठनों और पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढाएंगे तो वे और महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगी। महिलाओं के बीच संघ और भाजपा का जनाधार भी बढ़ेगा ,जो वोट बैंक बनकर मिशन 2024 में काम आयेगा।संघ के ओहदेदारो ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ संघ के विभिन्न अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की । विपक्षी गठबंधन एनडीए को घेरने की रणनीति पर भी बात की। दलित और पिछड़े वर्ग के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए भी संघ व भाजपा के संगठन मिलकर काम करने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भी मंथन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण, प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास सहित राष्ट्रवाद के अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने पर मंथन किया गया है।

पांच महीने में तैयार हुईं 11 लाख से अधिक घरौनियां

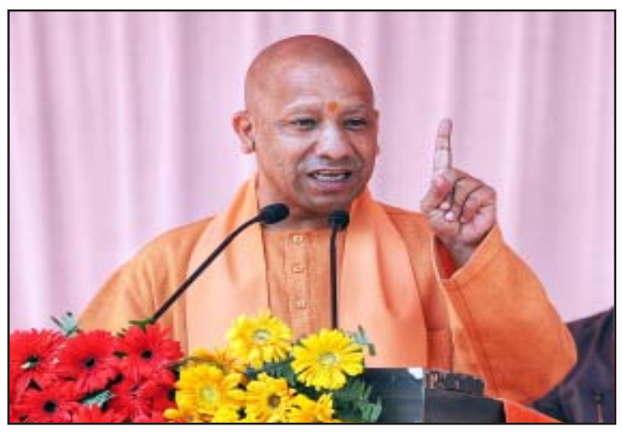

लखनऊ (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश में पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनियों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब तक 66 लाख से ज्यादा घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। प्रदेश के 90 हजार से अधिक गांवों के लिए घरौनियां तैयार कराई जा रही हैं, जिनमें से 47 हजार से अधिक गांवों की घरौनियों का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें भी प्रदेश के ललितपुर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर तक हर हाल में घरौनी बनाने के कार्य को शत प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य दिया है। सीएम योगी के द्वारा सीधी मॉनीटरिंग की वजह से प्रदेश में घरौनी बनाने के कार्य में तेजी देखने को मिली है। प्रतिमाह दो लाख घरौनी बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष बीते 45 दिनों में 4,31,794 से अधिक घरौनियां बनाई गई हैं, जो 144 प्रतिशत तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। बता दें कि प्रदेश में ड्रोन सर्वे के आधार पर 90,908 गांवों के लिए घरौनी बनाने का कार्य चल रहा है। अब तक 47,893 गांवों के लिए घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। 24 अप्रैल से 15 सितंबर तक 11,44,936 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं। वहीं 24 अप्रैल 2020 को योजना की शुरुआत होने से लेकर 15 सितंबर 2023 तक प्रदेश में 66,59,905 घरौनियां बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। स्वामित्व योजना में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में ललितपुर सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसके बाद कासगंज, मुरादाबाद, जालौन और संभल टॉप 5 जिलों में शामिल है। इन सभी जिलों में लक्ष्य के सापेक्ष 99 फीसदी से ज्यादा कार्य संपन्न हुआ है।

फ्लैट बेचने का मामला, ईडी ने नुसरत जहां से मांगे अतिरिक्त दस्तावेज

एजेन्सी

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को टीएमसी सांसद नुसरत जहां से 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ उनके जुड़ाव के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज मांगे हैं।

यह एक वित्तीय इकाई है, जिस पर वरिष्ठ नागरिकों को उचित दरों पर आवासीय फ्लैट देने का वादा करके कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी सांसद नुसरत जहां 12 सितंबर को मामले में पूछताछ के लिए कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में साल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय गईं थी।

इस दौरान उनके पास उक्त इकाई के पूर्व निदेशक के रूप में उनके संघ से संबंधित दस्तावेजों और कागजात वाली एक फाइल थी। हालांकि, उस दिन उन्होंने वे सभी दस्तावेज जमा नहीं किये, जो उनसे इस मामले में मांगे गए थे। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने अब अभिनेत्री से नेता बनीं नुसरत जहां से और दस्तावेज मांगे हैं।

सूत्रों के अनुसार, उस दिन नुसरत जहां द्वारा पेश दस्तावेजों में उक्त इकाई के साथ उनके जुड़ाव के साथ–साथ आय–व्यय विवरण पर स्पष्टता का अभाव है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। 12 सितंबर को ईडी अधिकारियों ने नुसरत जहां से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। ईडी दफ्तर से निकलते समय सांसद ने मीडिया से कहा था कि उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और जरूरत पड़ने पर भविष्य में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उक्त वित्तीय इकाई के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक दरों पर आवासीय फ्लैट देने का वादा करके उनसे कई करोड़ रुपये एकत्र किए। हालांकि, शिकायत के अनुसार, उन्हें फ्लैट उपलब्ध कराने की बजाय, उनके पैसे का इस्तेमाल नुसरत जहां सहित निदेशकों द्वारा निजी आवासीय आवास खरीदने के लिए किया गया था।

अमित शाह ने कहा कि महिलाओं के बारे में चिंता करने का अधिकार सभी को है

नई दिल्ली (एजेन्सी)। लोकसभा में बुधवार को हंगामे के बीच एक ऐसा वाक्या हुआ, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। दरअसल, संसद के विशेष सत्र के तीसरे तीन महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी। विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दुबे जैसे ही खड़े हुए तो विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और किसी महिला सांसद के नहीं बोलने पर आपत्ति जताई, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिलाओं के बारे में भाइयों को भी आगे बढ़कर सोचना चाहिए। निचले सदन में 'संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023' पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने की। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे का नाम लिया और उन्होंने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य

शोर–शराबा करने लगे। विपक्षी दल महिलाओं को अधिकार देने से जुड़े विधेयक पर चर्चा में सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता के रूप में किसी महिला सदस्य को मौका नहीं दिए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। गृह मंत्री शाह ने इस पर कहा कि महिलाओं के बारे में चिंता करने का अधिकार सभी को है। उन्होंने सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम लेते हुए पूछा कि क्या महिलाओं की चिंता केवल महिलाएं ही करेंगी। पुरुष उनकी चिंता नहीं कर सकते हैं? आप किस प्रकार के समाज की रचना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि महिलाओं की चिंता और उनके हित के बारे में आगे बढ़कर भाइयों को सोचना चाहिए और यही इस देश की परंपरा है। निचले सदन में 'संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023' पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने की। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे का नाम लिया और उन्होंने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य शोर–शराबा करने लगे। विपक्षी दल महिलाओं को अधिकार देने से जुड़े विधेयक पर चर्चा में सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता के रूप में किसी महिला सदस्य को मौका नहीं दिए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। गृह मंत्री शाह ने इस पर कहा कि महिलाओं के बारे में चिंता करने का अधिकार सभी को है। उन्होंने सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम लेते हुए पूछा कि क्या महिलाओं की चिंता केवल महिलाएं ही करेंगी। पुरुष उनकी चिंता नहीं कर सकते हैं? आप किस प्रकार के समाज की रचना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि महिलाओं की चिंता और उनके हित के बारे में आगे बढ़कर भाइयों को सोचना चाहिए और यही इस देश की परंपरा है। निचले सदन में 'संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023' पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने की। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे का नाम लिया और उन्होंने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य शोर–शराबा करने लगे। विपक्षी दल महिलाओं को अधिकार देने से जुड़े विधेयक पर चर्चा में सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता के रूप में किसी महिला सदस्य को मौका नहीं दिए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। गृह मंत्री शाह ने इस पर कहा कि महिलाओं के बारे में चिंता करने का अधिकार सभी को है। उन्होंने सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम लेते हुए पूछा कि क्या महिलाओं की चिंता केवल महिलाएं ही करेंगी। पुरुष उनकी चिंता नहीं कर सकते हैं? आप किस प्रकार के समाज की रचना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि महिलाओं की चिंता और उनके हित के बारे में आगे बढ़कर भाइयों को सोचना चाहिए और यही इस देश की परंपरा है। दुबे ने कहा, 'कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह लोकतंत्र का गला घोंटते हैं, मैं इसका उदाहरण हूं।'

जयशंकर ने कनाडा मुद्दे पर पीएम मोदी को दी जानकारी

एजेन्सी

नयी दिल्ली खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक गतिरोध के मद्देनजर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटनाक्रम से अवगत कराया है। सूत्रों के मुताबिक, जयशंकर ने संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री से मुलाकात की और समझा जाता है कि उन्होंने उन्हें कनाडा से जुड़े घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए जब 18 सितंबर को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में आरोप लगाया था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और जून में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों की जांच सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने उसी दिन कहा था कि एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है। भारत ने मंगलवार को कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करते हुए ट्रूडो के आरोपों को श्वेतुका और प्रेरितश बताया था।

कावेरी विवाद पर सीएम सिद्दारमैया ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से की मुलाकात, पीएम से हस्तक्षेप की मांग

एजेन्सी

नयी दिल्ली। कावेरी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के संसद सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाम को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक होगी और बैठक के बाद विवाद पर भविष्य के कदम के बारे में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के पास दोनों राज्यों को बुलाने और उनकी बात सुनने का अधिकार है। इस पृष्ठभूमि में, हमने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है।" इससे पहले बैठक को संबोधित करते हुए सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि संकट फार्मूले के अभाव में कावेरी नदी जल बंटवारा राज्य के लिए संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि सवाल पानी छोड़ने का नहीं है, क्योंकि छोड़ने के लिए पानी ही नहीं है। सीएम सिद्दारमैया ने कहा, "हम सभी को राज्य की भूमि, भाषा, पानी और संस्कृति को बचाने और संरक्षित करने के लिए दलगत राजनीति को छोड़कर एकजुट होना चाहिए। हमें पीने के लिए 33 टीएमसी, खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए 70 टीएमसी और उद्योगों के लिए 3 टीएमसी पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। राज्य को हर हाल में 106 टीएमसी पानी की जरूरत है। ऐसे में राज्य के पास महज 53 टीएमसी का ही भंडारण है। ऐसे में तमिलनाडु को छोड़ने के लिए पानी नहीं है। उन्होंने कहा, "राज्य में अगस्त में बारिश नहीं हुई है। कर्नाटक राज्य संकट में है। सीएम सिद्दारमैया ने कहा, ऐसे में लोगों के हितों की रक्षा के लिए मेकेदातु परियोजना अनिवार्य है।

केरल को मिलने वाली है दूसरी वंदे भारत ट्रेन

एजेन्सी

तिरुवनंतपुरम केरल को जल्द ही अपनी दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। सूत्रों के अनुसार इसकी रविवार को शुरुआत हो सकती है। सूत्रों के अनुसार पूरी संभावना है कि ट्रेन रविवार को उत्तरी जिले कासरगोड से सुबह 7 बजे राज्य की राजधानी के लिए रवाना होगी और दोपहर 3.05 बजे पहुंचेगी। उसी दिन वापसी में यह शाम 4.05 बजे यहां से रवाना होगी और रात 11.55 बजे कासरगोड पहुंचेगी।

महिलाओं को वंदन की नहीं, सम्मान व समानता की जरूरत, डीएमके ने बिल को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना

एजेन्सी

नयी दिल्ली। द्रविण मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने बुधवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर महिला आरक्षण विधेयक को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि महिलाओं को पूजा और वंदन की जरूरत नहीं है, उसे समानता और सम्मान की जरूरत है। लोकसभा में 'संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक की सदस्य कनिमोझी ने इसका समर्थन किया और कहा, ''लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ने इसे भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। वर्ष 2024 के चुनावों को ध्यान में रखकर यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतीकों की राजनीति (टोकनिज्म) बंद होनी चाहिए। कनिमोझी ने कहा कि सरकार ने इस प्रस्तावित कानून को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा है, लेकिन महिलाओं को वंदन, पूजा की जरूरत नहीं है, उन्हें सम्मान की, समानता की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''इस देश में, इस संसद में महिलाओं का अधिकार उतना ही है, जितना पुरुषों का है। द्रमुक सदस्य ने कहा कि सबसे पहली बार महिला आरक्षण विधेयक 1996 में तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा उनकी पार्टी के सहयोग से लाया गया था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी विधेयक लाई थी, लेकिन इस विधेयक को राज्यसभा में कांग्रेस–नीत संप्रग ने पारित कराया। कनिमोझी ने कहा कि उन्हें 2010 में राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का मौका मिला था और आज 13 वर्ष बाद वह लोकसभा में इसी विधेयक पर अपने विचार रख रही हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि ने 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि 2017 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और द्रमुक नेता स्टालिन ने भी मोदी को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था। कनिमोझी ने कहा कि वह स्वयं भी इस विषय को कई बार संसद में उठा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि संसद में पूछे गये उनके प्रश्नों के उत्तर में सरकार की ओर से लगभग यही जवाब मिला कि इस पर विभिन्न हितधारकों से विचार किया जा रहा है और आम–सहमति बनाकर इसे लाया जाएगा। कनिमोझी ने कहा, ''सरकार ने कौन सी सहमति बनाई, बल्कि यह विधेयक तो गोपनीयता के साथ लाया गया।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रेम प्रसंग के वक्त बने शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं

एजेन्सी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को अपने एक बड़े फैसले में कहा कि इसे दुष्कर्म की कैटगरी में रख सकते। एक युवती की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है।

भारत को नेहरू मिले, पाक को जिन्ना, इसलिए हम इस मुकाम पर हैं : आम आदमी पार्टी

एजेन्सी

नयी दिल्ली भारत आज जहां है और जहां पाकिस्तान है उसका मूल कारण है कि भारत को आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले और पाकिस्तान को पहले प्रधानमंत्री के रूप में जिन्ना मिले। बुधवार को यह बात राज्यसभा में कही गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप कुमार ने यह बात कही। सदन में चंद्रयान और इसरो पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद नहीं किया गया तो वह बेमानी होगी। आजादी के बाद हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि कई जगहों पर खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं था, उस समय कोई व्यक्ति कैसे यह सोच सकता था कि पैसा स्पेस साइंस में लगाना है। राजनीतिक रूप से उनका बहुत विरोध हुआ होगा, लेकिन उन सारे विरोधों को अलग रखते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक दूर दृष्टि और स्पष्टता दिखाई, इसको कहते हैं लीडरशिप। उन्होंने सदन में कहा कि नींव का पत्थर अगर सीधा लगता है तो बाकी के पत्थर भी सीधे लगते जाते हैं और दीवार सीधी जाती है। यदि नींव का पत्थर टेढ़ा लगे तो दीवार भी टेढ़ी हो जाती है। संदीप कुमार ने कहा कि पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और फिर अटल बिहारी वाजपयी ने भी स्पेस साइंस को काफी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि इसरो इंस्टीट्यूशन के बिल्ड होने के 10 साल के अंदर ही सबसे पहले सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च कर दिया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 20 साल होते–होते भारत में जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, इंडिया में वह तैयार कर लिया था।

शराबबंदी वाले बिहार में थानों से शराब तस्करी!

एजेन्सी

पटना। शराबबंदी वाले बिहार राज्य में जब प्रदेश के थानों से ही शराब की तस्करी होने लगे तो फिर प्रश्न तो उठेंगे ही। बिहार के वैशाली और बक्सर जिले से ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल इस पर कारवाई कर ऐसे पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वैशाली जिले के सराय थाना में जब्त शराब रात के अंधेरे में चोरी से पिकअप पर लोड करते पटना उत्पाद विभाग की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उत्पाद विभाग की टीम ने घटना की जानकारी वैशाली एसपी रविरंजन को दी। सूचना पर पहुंचे एसपी रवि रंजन एवं हेडक्वार्टर डीसपी देवेंद्र कुमार ने घटना की जांच पड़ताल की। इसके बाद एसपी ने थाना अध्यक्ष विदुर कुमार, मालखाना प्रभारी मुनेश्वर कुमार, ड्यूटी में तैनात सुरेश कुमार एवं चौकीदार परमेश्वर राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जाता है कि बरामद शराब को नष्ट करने की बजाय इसे बेचने की तैयारी थी।विभिन्न कांडों में जब्त करीब 3,728.220 लीटर शराब को नष्ट किया जाना था, जिसमें करीब 2,782.590 लीटर शराब को नष्ट किया गया। शेष करीब 945.630 लीटर विदेशी शराब बेचने की फिराक में थे।

सम्पादकीय

आधी दुनिया का हक

यह सुखद संयोग ही है कि नई संसद का आगाज देश की नारी शक्ति को उसके दशकों से लंबित हक देने से हुआ है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा व विधानसभाओं में तैंतीस फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी थी। निस्संदेह, इसका देश–दुनिया में सकारात्मक संदेश जाएगा कि हम महिलाओं को उनके वाजिब हक देने को प्रतिबद्ध हैं। निस्संदेह, इस कदम से भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की सशक्त भूमिका होगी। यह प्रयास आम महिलाओं के सशक्तीकरण की राह भी खोलेगा। कह सकते हैं कि करीब तीन दशक से अटके महिला आरक्षण बिल को मूर्त रूप देने का नैतिक साहस राजग सरकार ने दिखाया। इससे लोकसभा में मौजूद 14 फीसदी व राज्यसभा में 12 फीसदी महिलाओं की स्थिति में अब सम्मानजक ढंग से इजाफा होगा। पहले संसद के विशेष सत्र को लेकर तरह–तरह के कयास लगाये जा रहे थे, अब लगता है कि विशेष सत्र बुलाना एक सार्थक कदम साबित होगा। राजग सरकार ने इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने महिला आरक्षण की वकालत की थी। इस बीच विभिन्न सरकारों में इस विधेयक को सिरे चढ़ाने की कोशिश हुई। फिर वर्ष 2010 में संप्रग सरकार ने इस घविधेयक को राज्यसभा में पारित किया था। लेकिन तब संप्रग सरकार में शामिल राजद, सपा व झामुमो आदि दलों ने इसमें जातिगत आरक्षण की मांग उठाकर विधेयक की गति थाम दी थी। वैसे सवाल उठाया जा सकता है कि वर्ष 2014 में महिला आरक्षण के मुद्दे को अपने घोषणापत्र में शामिल करने के बावजूद इसे मूर्त रूप देने में इतना वक्त क्यों लगा। क्या जब देश आम चुनाव की ओर बढ़ चुका है तब महिला आरक्षण के मुद्दे को अमलीजामा पहनाने की कवायद हुई है? एक पहलू यह भी है कि विधेयक के कानून का रूप लेने के बावजूद इसका क्रियान्वयन तब संभव होगा, जब देश में जनगणना के उपरांत होने वाला परिसीमन पूर्ण होगा। यानी महिला आरक्षण का लाभ आगामी आम चुनाव में संभव नहीं होगा।बहरहाल, जनप्रतिनिधि संस्थाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था होना भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़ी घटना होगी। बेहतर होगा कि संसद के नये भवन में इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल स्वस्थ चर्चा करें और आम सहमति बनाएं। इस तरह नया संसद भवन दोहरा इतिहास रचेगा। यद्यपि राजग सरकार ने विधेयक के मसौदे पर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी नहीं दी है, कयास लगाये जा रहे हैं कि इसके मूल स्वरूप को बरकरार रखने की कोशिश होगी। अब देखना होगा कि जिन मुद्दों पर लंबे समय तक महिला आरक्षण का विरोध किया जाता रहा है, उन्हें किस तरह संबोधित किया जाता है। हालांकि, तब विरोध करने वाले राजनीतिक दल फिलहाल दबाव बनाने की स्थिति में नहीं हैं। जिनके विरोध के चलते ही महिला आरक्षण बिल को पांच बार पारित करने की असफल कोशिश हो चुकी है। बहरहाल, इस बिल के पारित होने से देश में लैंगिक समानता आएगी। इस समय दुनिया में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की औसतन हिस्सेदारी 26 फीसदी है, जबकि वर्तमान में भारत में यह प्रतिशत 15.21 है। वहीं राज्य विधानसभाओं में स्थिति और ज्यादा खराब है, किसी भी राज्य में 15 फीसदी महिलाओं की भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी नहीं बन पायी। बहरहाल, नये विधेयक के कानून बनने के बाद भारतीय जनप्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी तैंतीस फीसदी हो जाएगी। वैसे तो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में महिला जनप्रतिनिधियों की विशिष्ट भूमिका रही है। जिन्होंने न केवल सदन की गरिमा बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में रचनात्मक योगदान भी दिया। देश की संसद के दोनों सदनों में पिछले साढ़े सात दशकों में करीब छह सौ महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। बहरहाल, देर आए दुरुस्त आए, की तर्ज पर इसे भारतीय लोकतंत्र की शुभ शुरुआत कहा जा सकता है। इसके बावजूद उम्मीद करें कि जमीन से जुड़ी व महिला सरोकारों को प्रतिबद्ध महिलाएं ही जनप्रतिनिधि सदनों में पहुंचें। ऐसा न हो कि पहले से मौजूदा राजनीति में सक्रिय राजनीतिक घरानों के नेता इस पहल को अपने परिवार की महिलाओं के नाम पर राजनीति करने के अवसर में ही बदल दें।

आधी आबादी' के आरक्षण का दाव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में इतिहास बदलने की क्षमता भी है और इच्छा शक्ति भी है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा ही दृढ़शक्ति का परिचय दिया है। नरेन्द्र मोदी हमेशा राजनीतिक धुरंधरों और देशवासियों को चौंकाते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया है कि सभी हैरान रह गए हैं। नई संसद में विशेष सत्र शुरू होते ही मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया है। अब इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का लम्बे अर्से से इंतजार किया जा रहा था। पिछले कुछ सालों से चुनावों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से कहीं ज्यादा रहा है। मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को हक दिलाने का ऐसा दाव खेला है जो बड़ों–बड़ों को चित्त कर देगा। विशेष सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक लाने और उसे पारित करने की जोरदार वकालत की है लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। लगभग 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जरूर हुई। क्योंकि यह विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है। इसलिए यह इतना आसान भी नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि यह विधेयक पारित होते ही संसद का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा इस विधेयक का समर्थन किया। हालांकि कुछ अन्य दलों ने महिला कोटा के भीतर ओबीसी आरक्षण की कुछ मांगों को लेकर इसका विरोध किया। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था। जब मनमोहन सिंह शासन के दौरान राज्यसभा ने हंगामे के बीच इस बिल को पारित कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था जिन्होंने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि यह विधेयक रद्द हो गया क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। 2008 से पहले इस बिल को 1996, 1998, 1999 में पेश किया गया था। गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति ने 1996 के विधेयक की जांच की थी और सात सिफारिशें की थी। तब से यह बिल लटका ही पड़ा है। 2010 में जब यह विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया था तब समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, राजग के लालू प्रसाद यादव के कड़े घविरोध के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सक तब कई नेताओं ने विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए कोटा के भीतर कोटा की मांग की थी। इससे पहले 1993 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया था जिसमें पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई थी। इसके अलावा देश के कम से कम 20 राज्यों में पंचायत स्तर पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। वर्तमान में 70वीं लोकसभा में केवल 15 प्रतिशत महिला सांसद हैं और राज्यसभा में सिर्फ 12.2 प्रतिशत महिला सांसद हैं। यह वैश्विक औसत से 25.5 प्रतिशत से काफी कम है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विरोधियों का मानना है कि इससे केवल शहरी महिलाओं को फायदा होगा और इससे ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाएगी। 1998 में जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश ध किया गया था तब जहानाबाद के राजद सांसद सुरेन्द्र यादव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी के हाथों से बिल की कापी लेकर फाड़ दी थी। लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 है। वहीं महिला सांसदों की संख्या 78 है, इसका मतलब लगभग 14 प्रतिशत महिला सांसद हैं। जबकि राज्यसभा में 250 में से 32 सांसद ही महिला हैं यानी 11प्रतिशत हैं। वहीं मोदी सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी 5प्रतिशत के आसपास है। अगर ये विधेयक लागू हो जाता है तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 तक हो जायेगी। महिला आरक्षण समर्थकों का कहना है कि अगर महिलाओं को संसद में पुरुषों के बराबरी का स्थान मिल जाता है तो विश्व में भारत की छवि बेहतर हो जाएगी।

हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। इस विधेयक के फायदों पर गौर करें तो इससे भारत की महिलाएं ज्यादा सशक्त होंगी। लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव कम होगा। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। संसद मात्र पुरुष सत्ता का केंद्र भर सीमित नहीं होगा और राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी में भी इजाफा होगा। साथ ही दुनिया में भारतीय महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा।फिलहाल यह बिल पारित कराने में सभी राजनीतिक दलों में इच्छाशक्ति का अभाव नजर आ रहा है। देश की आधी आबादी को अपना हक कब मिलेगा इसका जवाब हमेशा गोल–मोल ढंग से दिया जाता रहा है। कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो 10 प्रतिशत से भी कम है। महिला आरक्षण पर सुगबुगाहट तो तेज होती है।

लगभग सभी राजनीतिक दल विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का समर्थन करते हैं लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही निकलता है। महिला संगठन अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन भी करते रहे हैं लेकिन यह बिल दांव–पेचों के चलते लटकता ही रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर है कि सभी राजनीतिक दल इस पर स्वस्थ चर्चा कर इस विधेयक को पारित कराएं और देश की आधी आबादी का सपना साकार करें। जैसा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि महिला के सशक्तिकरण से परिवार और समाज सशक्त होता है।

नारी शक्ति वंदन उर्फ महिला आरक्षण

चुनावी साल में हार की आशंकाओं के बीच जूझ रही भाजपा ने 19 सितम्बर को फिर एक चुनावी दांव चला। दांव पुराना था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने चलन के अनुरूप उस पर नया मुलम्मा चढ़ाकर इस तरह पेश किया, मानो यह उसी की पहल हो। 19 सितम्बर, 2023 को संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन संसद के नए भवन से कामकाज शुरु हुआ। मोदी सरकार ने इसके लिए गणेश चतुर्थी का दिन ही क्यों चुना, ये समझना कठिन नहीं है। हिंदुओं के लिए गणेश चतुर्थी का दिन खास मायने रखता है। पहले गणेश उत्सव महाराष्ट्र के अलावा कुछ गिने–चुने राज्यों में ही धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन सिनेमा और टीवी की पहुंच और प्रभाव के कारण धीरे–धीरे सारे देश में इसका दायरा बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी इस दिन को राजनैतिक तौर पर भुनाने की कोशिश अब तक किसी सरकार ने नहीं की। श्री मोदी यहां भी कीर्तिमान स्थापित कर गए। गणेश चतुर्थी के दिन संसद में प्रवेश से पहले, वे सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन पंडितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बीच कर चुके हैं और दोनों ही अवसरों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न होना कई सवालों को खड़े कर देता है। राष्ट्रपति महोदया को इन महत्वपूर्ण अवसरों पर मोदी सरकार ने क्यों शामिल नहीं किया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन एक बात दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट है कि संसद के कामकाज में भगवान और पूजा पाठ शामिल कर मोदी सरकार ने संविधान की भावना का अनादर किया, जो धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करता है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी इस मंच को एक धर्म तक समेटने की कोशिश की, ताकि इसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल सके। श्री मोदी के पास जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन का मौका अभी बचा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी सत्ता के हिलने का अहसास होने लगा है और इसलिए वे इस वक्त किसी भी मौके को चूकना नहीं चाहते।

संसद में कई दशकों से महिला आरक्षण पर कानून बनाने की मांग हो रही है। मोदी सरकार ने अपने 9 सालों के कार्यकाल में तो अब तक इस पर कुछ नहीं किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब साल भर भी नहीं बचे हैं, तो श्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम का जिक्र संसद में किया और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। मौजूदा समय में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है। और इस वक्त महिला सांसदों की संख्या 82 है। विधेयक में संविधान के अनुच्छेद– 239 एए के तहत

राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यानी, दिल्ली विधानसभा में भी 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। जो लोकसभा या विधानसभा सीट महिलाओं के एक चुनाव में आरक्षित होगी अगले चुनाव में वही सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी। बल्कि अन्य 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद जो तीसरा चुनाव होगा उसमें बची हुई 33 प्रतिशत सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस विधेयक के ऐसे प्रावधानों को सुनकर लगता है कि देश में कोई अभूतपूर्व क्रांति होने वाली है। महिलाओं को एकदम से शक्ति मिलने वाली है। एक झटके में सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, महिला विरोधी मानसिकता ठीक हो जाएगी। लेकिन हकीकत फिलहाल ऐसी नहीं है। विधेयक के मसौदे पर में यह लिखा है कि इसे संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रारंभ होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होनेके बाद लागू किया जा सकेगा। इसे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या पुनर्निर्धारण के बाद लागू किया जाएगा। लागू होने के बाद अधिनियम 15 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

अगली जनगणना कब तक होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में शायद जनगणना के आंकड़े जुटाना है ही नहीं। जब तक जनगणना नहीं होगी, तब तक महिला, पुरुष, अजा, जजा, ओबीसी इन सब के ताजा आंकड़े नहीं आएंगे और जब आंकड़े ही नहीं होंगे, तो आरक्षण की व्यवस्था किस तरह होगी, ये बड़ा सवाल है। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और कानून लागू होने के बाद पहली जनगणना के बाद ही संभव हो पाएगा। इसका यही मतलब है कि संसद के नए भवन में प्रवेश के साथ ही मोदी सरकार ने जिस तरह महिला आरक्षण को एक नए नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ पेश किया, वो सभी दलों से विचार–विमर्श के बाद पूरी तैयारी के साथ पहले या बाद में भी पेश हो सकता था, लेकिन सरकार ने इसी दिन को चुना ताकि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। श्री मोदी ने इस विधेयक के बारे में बोलते हुए कहा भी कि ईश्वर ने इस शुभ काम के लिए शायद मुझे चुना है। इस वक्तव्य में श्रेय बटोरने की हड़बड़ी साफ दिखाई देती है। क्योंकि मोदी सरकार ये जानती है कि महिला आरक्षण का विचार राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल से ही पनपना शुरु हुआ है, और बाद की तमाम सरकारों ने अपने–अपने स्तरों पर इसे पारित करवाने की कोशिश की।

2010 में सोनिया गांधी के प्रयासों से राज्यसभा तक में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया, लेकिन तब राजद, सपा जैसे दलों की कुछेक आपत्तियों के कारण लोकसभा में लटक गया। महिला आरक्षण विधेयक के लटकने–अटकने का इतिहास तो सबको ज्ञात है, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसके नाम पर भटकाने का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। सरकार ने यही इशारा दिया है कि केवल वही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है, जबकि यह पूरा सच नहीं है। आधे–अधूरे सच और आधी–अधूरी तैयारियों के साथ महिला आरक्षण या नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस दिशा में बढ़ता है और किस दशा को प्राप्त होता है, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा।

मोदी का मेक इन इंडिया हिट' और जी–20 'सुपर हिट'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थीम 'मेक इन इंडिया पूरी दुनिया में सिर चढ़ कर बोल रहा है। पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन ने अपने यहां एक समारोह में रूस वालों से अपील की कि अगर तरक्की करनी है तो हमें 'मेक इन इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी को अपनाना होगा। दरअसल वे अपने यहां ईस्टर्न इकोनॉमिक फार्म में बोल रहे थे और उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि उन्हें रूस में बनी कारें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का 'मेक इन इंडिया थीम सराहनीय है जिसके दम पर भारत के प्रोडक्ट्स दुनियाभर में छा रहे हैं। जी–20 सम्मेलन की सफलता तो भारत के लिए ऐतिहासिक है ही लेकिन इस सम्मेलन के फौरन बाद पुतिन का यह बयान बहुत अहमियत रखता है। हमारा मानना है कि मेक इन इंडिया के तहत सूई से लेकर जहाज निर्माण तक भारत सबकुछ राष्ट्रीय स्तर पर बना रहा है। यही वजह है कि हमारा आयात–निर्यात अलग ही बुलंदियों के रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ऑटो इंडस्ट्री, कपड़ा, टीवी, औद्योगिक ढांचा, मोबाइल कल तक हमें तकनीक तक बाहर से लेनी पड़ती थी लेकिन मोदी सरकार के चलते अब 'मेक इन इंडिया मंत्र के तहत घरेलू उत्पादन तेजी से तरक्की की राह पर है। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार, उनके सहयोगियों को बधाई देनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि इसे किसी राजनीति से नहीं बल्कि भारतीयता के तहत देखा जाना चाहिए अर्थात यह भारत की एक बड़ी जीत है और ऐसी उपलब्धि है जिस पर प्रत्येक नागरिक गर्व महसूस कर सकता है। यह 'मेक इन इंडिया का ही कमाल के व्हाट्सऐप का चौनल फीचर अब भारत में भी आ चुका है वरना कल तक इसकी शुरूआत अमरीका समेत दस देशों में हुई थी लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने इसमें भारत को भी शामिल कर लिया है और अब सोशल मीडिया प्रेमी किसी भी चौनल को फॉलो करने के लिए सर्च डायरेक्टरी में जाकर अपने शौक के मुताबिक स्पॉर्ट्स टीमों का अपडेट प्राप्त कर सकेंगे। जब एक देश का दुनिया में नाम गूंजता है तो उसे कोई भी नजरंदाज नहीं कर सकता। आओ अब भारत में संपन्न हुए जी–20 समिट की सफलता की बात कर लें कि किस तरह से हमने इतिहास रचा है। दुनियाभर के अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और रूस जैसे देशों के साथ पीएम मोदी ने अफ्रीकी देशों को भी जोड़ दिया। अफ्रीकी देशों को इसका सदस्य बनाकर पीएम मोदी ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया की सर्वशक्तिमान ताकतों में भारत की एंट्री लगभग तय है। अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और कनाडा व आस्ट्रेलिया अब भारत के बिना नहीं चल सकते। चाहे अमरीकी राष्ट्रपति बाइडेन हो या फ्रांस के राष्ट्रपति मेक्रों हो या फिर यूके के प्रधानमंत्री सुनक हो या फिर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हो भारत की मेजबानी में जी–20 के प्रस्तावों को हर किसी ने सराहा। संदेश यही था कि आर्थिक विकास के लिए पूरी दुनिया को एक होना होगा। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन के साथ–साथ मूल्य नियंत्रण और आर्थिक मंदी को लेकर सभी प्रस्ताव इसमें रखे थे और पूरा समर्थन मिला। हालांकि सबसे बड़ी बात रूस–यूक्रेन युद्ध को लेकर थी और इस मामले में भी यह बात स्पष्ट की गई कि युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है। दुनिया के विकास का मार्ग युद्ध से होकर नहीं गुजरता बल्कि एक–दूसरे के करीब आने से एक धरती, एक विश्व, एक परिवार अर्थात वासुदेव कुटुंबकम के मंत्र पर दुनिया को चलना होगा।

भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी देशों को अपने साथ जोड़कर और विशेष रूप से साउदी अरब के प्रिंस सलमान के साथ भारत ने जो ऐतिहासिक समझौते किए वह काबिले तारीफ है। मीडिलईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कारिडोर को लेकर पीएम मोदी के आह्वान को ताकत मिली है और भारत से यूरोप तक जब रेल मार्ग बन जायेगा तो रास्ते में पड़ने वाले देशों को ऊर्जा और ईंधन की जरूरत भारत के इस प्रस्ताव से पूरी हो जायेगी। भारत–साऊदी अरब कर्मिशयल मार्ग के लिए साऊदी अरब के प्रिंस ने बीस अरब डॉलर की धनराशि भी पेश की है। कुल मिलाकर सभी राष्ट्र इस आयोजन के लिए भारत के पीएम को बधाई दे रहे हैं और खुद पीएम मोदी ने इस समिट की सफलता के लिए सरकार के पुलिस से लेकर गार्ड तक, संत्री से लेकर मंत्री तक हर किसी को बधाई दी है और इसी मंत्र के साथ दुनिया के नक्शे पर भारत का शांति का संदेश भी दिया है। तो इसलिए 'मेक इन इंडिया को हमारी कलम का सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद–जय भारत।

पाकिस्तान के नापाक इरादों को समझे भारत

आर विक्रम सिंह

जम्मू–कश्मीर में अनंतनाग के कोकेरनाग में आतंकियों से लंबी खिंची मुठभेड़ ने हमें यह मानने को मजबूर कर दिया है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास के बाद भी स्थितियां अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई हैं। यही प्रदर्शित करना पाकिस्तानी सत्ता और विशेष रूप से उसके डीप स्टेट की मंशा भी है। कोकेरनाग कोई सीमा क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की सीमा से लगभग डेढ़–दो सौ किमी अंदर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। आतंकियों को यहां आने के लिए सीमा के आगे पूरा राजौरी जिला पार करना पड़ा होगा। जम्मू श्रीनगर हाइवे 44 के पश्चिम में 40 किमी और अंदर आने पर कोकेरनाग वन क्षेत्र प्रारंभ होता है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आतंकी संरचना और स्थानीय सहयोग बरकरार है। अनंतनाग में मुठभेड़ के बीच उड़ी सेक्टर में भी सीमा पार करने का प्रयास करते तीन आतंकी मारे गए। पिछले दस दिनों में सीमा पार से घुसपैठ के कम से कम पांच प्रयास सुरक्षा बलों ने असफल किए हैं। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लांच पैड सक्रिय हैं। पाकिस्तान जैसे–जैसे विदेशी सहायता के सहारे अपने आर्थिक संकट से निकलता दिख रहा है, वैसे–वैसे वह पहले की तरह कश्मीर को अशांत करने में जुट रहा है। खबरें हैं कि सीमाओं पर सख्ती के बाद आतंकियों के आने के नए रास्ते पंजाब और नेपाल से बन रहे हैं। पाकिस्तान हथियार और बारूद ड्रोन के माध्यम से भेज कर आंतकी गतिविधियों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वित्तीय व्यवस्था के लिए ड्रोन से ड्रग्स की तस्करी आतंकी नेटवर्क का बड़ा सहारा है। जी 20 शिखर सम्मेलन से पहले भी आतंकियों की घुसपैठ के अनेक प्रयास हुए, लेकिन सीमा रक्षकों की सजगता ने कुछ होने नहीं दिया। इस बार आतंकी कोकेरनाग के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने में सफल हो गए। एक और परिवर्तन ध्यान देने योग्य है। पीर पंजाल के पर्वतीय सीमांत और आंतरिक क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। आतंकियों के निशाने पर अब सुरक्षा बल हैं। उनके लिए कश्मीर घाटी में ही हमला करना आवश्यक नहीं है। यह भी प्रतीत हो रहा है कि आतंकी संगठनों के नेटवर्क का विस्तार पहले जैसा ही है। सवाल समस्या के समाधान का है। आखिर कब तक यह सब चलने वाला है? आजादी के आंदोलन के दौरान जिन्ना ने मजहब आधारित राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग–अलग राष्ट्र हैं। मूलतः इस विचार के प्रणेता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इस विचारतंत्र को अंग्रेजी सत्ता की बैसाखियां मिलीं। कांग्रेस इस पाकिस्तानी विचार के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकी। इस तरह विश्व का पहला मजहब आधारित देश पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। चूंकि महाराजा हरि सिंह का कश्मीर क्षेत्र मुस्लिम बहुल था, इसलिए वह पाकिस्तान का निशाना बना। जम्मू–कश्मीर का 86 हजार वर्ग किमी क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में 1947–48 से चला आ रहा है। यह यथास्थिति इसलिए है, क्योंकि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने कभी भी उसे बदलने का प्रयास नहीं किया। यह वह क्षेत्र है, जो अनायास हुए युद्धविराम के कारण भारत के पास आने से रह गया। वास्तव में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की कोई रुचि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की नहीं थी। जब भी उन्हें पाकिस्तान से वार्ता का अवसर मिला, उन्होंने युद्धविराम रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। सिंधु जल समझौते के समय पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब ने और फिर 1963 में भारत–पाक वार्ताओं के दौरान भुट्टो ने भी यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्हें तो पूरा कश्मीर चाहिए था। भुट्टो ने भारतीय प्रतिनिधि स्वर्ण सिंह से कहा भी था कि अब तो बस युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। कश्मीर को पाकिस्तान अपने अस्तित्व की आधारभूत शर्त मानता है। भारत–पाकिस्तान की तरह जम्मू–कश्मीर को भी विभाजित करने की भारतीय नेताओं की मानसिकता ने समस्या के समाधान में भारतीय पक्ष को कमजोर ही किया। अहिंसा की कोख में पले नेताओं में रणनीतिक सोच, भूराजनीतिक ज्ञान और पाकिस्तान के मजहबी लक्ष्यों की समझ के अभाव ने हमारे नेतृत्व को कश्मीर समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकने का कोई अवसर ही नहीं दिया। वे कश्मीरियत की बात करते रहे और पाकिस्तान अपना आतंकी मजहबी नेटवर्क सशक्त करने में लगा रहा। हमने कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए नया वैकल्पिक जमीनी नेतृत्व खड़ा करने के बजाय परिवारवादी नेताओं के भरोसे हवाई हल तलाशने में बड़ा समय बर्बाद किया। हमारी हर कोशिश तुष्टीकरण की चौखट पर आकर दम तोड़ देती रही। इसमें संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू–कश्मीर में चतुर्दिक गुणात्मक परिवर्तन आया है। आतंकी गतिविधियों में 2016–19 की तुलना में 2019–22 में 32 प्रतिशत की कमी आई है। सुरक्षा बल अधिक सुरक्षित हुए हैं। उन्हें जन सहयोग भी बहुत मिल रहा है। इसके बाद भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मजहबी पाकिस्तान भविष्य में भी हमारे लिए कश्मीर संकट का कारण बना रहेगा। पाकिस्तान, जो बना ही मजहब के लिए है, से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह कभी पंथनिरपेक्षता को समझेगा।

दंगल में सवा सौ पहलवानों ने दिखाया दमखम

धर्मापुर के सौरभ यादव ने जीता जौनपुर केसरी का खिताब

विजेता उपविजेता को पुरस्कार स्मृति चिन्ह गदा भेटकर किया सम्मानित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सरायख्वाजा के कुकुडीपुर के प्रसिद्ध दंगल में सवा सौ पहलवान ने जोर अजमाइश की। जिसमें फाइनल राउंड में धर्मापुर अखाड़ा के पहलवान सौरभ यादव ने अमित यादव को पछाड़कर जौनपुर केसरी का खिताब जीतकर विजेता बने। विजेता उपविजेता पहलवान को केसरी फीता, गदा स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

पूर्व विधायक स्वरू राजबहादुर यादव की स्मृति में कुकुडीपुर के प्रसिद्ध दंगल में सवा सौ पहलवानो ने अखाडे पर दांवपेच अजमाए। जिसमें फाइनल राउंड में धर्मापुर अखाड़ा के सौरभ यादव ने जिला केसरी की किताब पर कब्जा किया। जबकि उपविजेता अमित यादव रहे। जिला बाल केसरी

खिताब पर त्रिलोचन के विवेक यादव ने बाजी मारी ।दूसरे स्थान पर नेताजी अखाड़ा गोबरा के प्रियांशु कुमार रहे। जिला अभिमन्यु खिताब पर त्रिलोचन के विकास यादव ने कब्जा किया और वहीं उपविजेता धर्मापुर के अमरदीप रहे। जबकि जिला कुमार के खिताब पर धर्मापुरा अखाड़ा जमीन पकड़ी के अजय यादव ने कब्जा किया । केराकत नई बाजार के सूरज कुमार दूसरे स्थान पर रहे। इसके के पूर्व क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल राउंड की कुश्ती प्रतियोगिता हुई। जिसमें सैकड़ो पहलवानों ने अपने दमखम कला कौशल का प्रर्दशन किया ।

विजेता उपविजेता पहलवानों को केशरी खिताब, पुरस्कार के साथ–साथ गदा स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। विजेता पहलवान को पुरस्कार वितरण समाजसेवी सुभाष चंद्र यादव, लालचंद यादव लाले, डॉ जितेंद्र यादव, विवेक यादव, डॉ आलोक यादव ने देकर सम्मानित किया। रेफरी की भूमिका में इंटरनेशनल कोच कृष्णकांत, कमलेश कुमार यादव, शाही कोच अशोक यादव रहे। सहायक निर्णायक लालजी यादव लक्ष्मण यादव रामसेवक यादव रहे। संचालन मग्घू पहलवान ने किया। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह भारत अमीन राजेंद्र सिंह अमित यादव रमाशंकर राजेश कुमार रतन कुमार, चंदन यादव अशोक कुमार मौजूद रहे।

सिटी एकेडमी लॉ कॉलेज ने, पीसीएस-जे परीक्षा में उच्च रैंक हासिल कर अभूतपूर्व सफलता हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं का किया अभिनंदन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। सिटी एकेडमी लॉ कॉलेज हमेशा छात्रों को ज्ञान के क्षेत्र में गौरवशाली ऊंचाइयों को छूने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए उनकी सराहना करने में विश्वास रखता है। इसका उद्देश्य छात्रों को व्यापक दुनिया के लिए एक दिशा देना और उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए अटूट मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना है। कॉलेज ने पीसीएसजे में अपने छात्रों की अनुकरणीय उपलब्धियों को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि नम्रता पाठक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की धर्मपत्नी द्वारा ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इस समारोह के बाद सीजीसी की अध्यक्ष डॉ. ऐश्वर्या सिंह ने स्वागत भाषण दिया। कॉलेज ने अपने उन दिग्गजों को सम्मानित किया जिन्होंने पीसीएस–जे

परीक्षा में उच्च रैंक हासिल कर अभूतपूर्व सफलता हासिल की। अलका भारती, सृष्टि सिंह, रूपल तिवारी, लाल चंद्र मिश्रा, शिवम सिंह और विनय कुमार सिंह ने क्रमशः पीसीएस–जे और एपीओ परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज का नाम रोशन किया। चूँकि माता–पिता अपने बच्चों के सपनों को साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हर प्रशंसा के पात्र हैं. इन सफल विद्यार्थियों के माता–पिता को प्रोफेसर बी.डी. सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। श्री सिंह को 50 न्यायाधीशों और 60 एपीओ को तैयार करने का बड़ा श्रेय है जो देश भर में न्यायपालिका को सक्रिय रूप से अपनी ईमानदार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कॉलेज के पूर्व छात्र जीशान मसूद, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बसंत कुमार जैन, बेंच मजिस्ट्रेट, और अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न्यायपालिका में मील के पत्थर स्थापित किए हैं, को तेजेश्वर पाण्डेय सहायक निदेशक रणनीति द्वारा सम्मानित किया गया। अमृत श्रीवास्तव. कॉलेज ने सीजीसी के युवा उपलब्धि हासिल करने वालों को भी सुविधा प्रदान की। इन मेधावी विद्यार्थियों को विशिष्ट अतिथि प्रो. सीपीसी सिंह, प्रो. आनंद विश्वकर्मा द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आजाद कुमार द्विवेदी थे। सभी प्रतिष्ठित अतिथियों ने कॉलेज को उसके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और छात्रों को अपना आशीर्वाद दिया और आने वाले दिनों में इसके शानदार भविष्य की कामना की। समारोह में मुख्य भाषण मुख्य अतिथि नम्रता पाठक द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन डॉ. ममता श्रीवास्तव निदेशक सीजीसी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। जिन्होंने कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों और उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद दिया। उक्त जानकारी

सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज की शिक्षिका अनीता गौतम ने दी।

भाजपा की डबल इंजन सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही है : रीबू श्रीवास्तव

भाजपा शासन में महिला सुरक्षित नहीं है : रीबू श्रीवास्तव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। समाजवादी महिला सभा की जिला कार्यकारिणी कमेटी घोषित किया गया। मुख्य अतिथि समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रिबू श्रीवास्तव रही। नवनियुक्त पदाधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि महिलाओं का सम्मान स्वाभिमान की रक्षा सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर सकतीं है भाजपा सरकार ने सिर्फ महिलाओं को अपमानित किया है। भाजपा शासन में महिला सुरक्षित नहीं है।आये दिन महिलाओं पर अत्याचार हत्या जैसी घटना आम हो गयी है भाजपा सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाता बल्कि दोषियों की मदद किया जाता हैं। साथ ही उन्होंने कहा भाजपा ने विकास के दावे तो बहुत किए पर जमीन पर उसकी कहीं छाया तक नहीं दिखाई देती है। भाजपा का एजेण्डा जनता के हितों और समस्याओं से सम्बन्धित नहीं होता है। नतीजतन महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ने से हर ओर अराजक स्थिति पैदा हो रही है। हर कोई परेशान है। जनहित में कोई कदम उठाने के बजाय भाजपा अपने पुराने वादों और अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए नए तमाशे और इवेंट करती रहती है ताकि जनता उनकी चकाचौंध में बहकी रहे।

भाजपा की डबल इंजन सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही है।

वह सत्ता में बने रहने के लिए पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को ही लागू कर रही है। भाजपा सरकार समाजवादी सरकार के कामों को विज्ञापन जारी कर अपना बताने में लगी है।

अध्यक्षता करते निवर्तमान जिलाअध्यक्ष डां अवधनाथ पाल ने कहा महिलाएं अब जाग गई है भाजपाई खेल तमाशों से बहकने और भटकने वाली नहीं है। वह सन् 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को उसके झूठे वादों की याद न केवल दिलाएगी बल्कि झूठे वादे करने वाली भाजपा सरकार को भी हटायेगी। महिला सभा की जिलाअध्यक्ष शर्मिला यादव ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया।। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, सुमन यादव, मालती निषाद, आरती यादव, तारा त्रिपाठी, सीमा, संगीता,उजमा खान, सोनी यादव, सोनी सेठ,सीमा यादव,पूनम दूबे,आरती, श्रीवास्तव,शुशीला गौतम, सबीना, अनन्ता नाविक, शकुंतला, पूजा, राजकुमारी,राजेन्द्र टाइगर, राहुल त्रिपाठी, इर्शाद मंसूरी, अनील दूबे, आदि लोग उपस्थित रहे।

साहित्य की लोकमंगल यात्रा पर परिसंवाद आज

टाउन हाल में सायं 6 बजे से आयोजित परिसंवाद में दो शून्य रहेगा चर्चा का आकर्षण

लखनऊ के ए पी सेन हाल में साहित्य की लोकमंगल यात्रा पर परिसंवाद 23 सितम्बर को

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

गोण्डा। श्री लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री महाविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष एवं शोध केन्द्र के निदेशक डा. शैलेन्द्र नाथ मिश्र के संयोजन में शुक्रवार को सायं 6 बजे से संपूर्णानन्द स्मारक टाउन हॉल में साहित्य की लोकमंगल यात्रा को लेकर साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति में परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजक डा शैलेन्द्र नाथ मिश्र ने बताया कि आगामी 4 अक्टूबर को मगहर अगोना व तुलसी जन्मभूमि सूकरखेत गोण्डा तक निकाली जा रही साहित्य की लोकमंगल यात्रा कार्यक्रम की तैयारी की चर्चा के क्रम में गोण्डा व लखनऊ में दो परिसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें टाउन हॉल के परिसंवाद का मुख्य आकर्षण दो शून्य विषयक चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त 23 सितंबर को लखनऊ के एपी सेन हाल में साहित्य की लोकमंगल यात्रा पर चर्चा की जाएगी।

कार्यक्रम के उद्देश्य व लक्ष्य पर चर्चा करते हुए डा. मिश्र ने बताया कि साहित्य का भूगोल विषयक शोध को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म दिवस 4 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे से एक दिवसीय यात्रा कबीर निर्वाण स्थली मगहर से निकाली जाएगी जो राम जानकी मार्ग से होकर आचार्य शुक्ल की जन्मभूमि अगोना जनपद बस्ती और पुनरू वहां से अयोध्या नवाबगंज मार्ग से तुलसी जन्मभूमि राजापुर सूकरखेत गोण्डा में सम्पन्न होगी। उन्होंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिन्दी साहित्य के ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य में लोकमंगल एवं साहित्य की रचना प्रक्रिया में अन्तरूसूत्र के रूप में विरुद्धों के सामंजस्य–समन्वय की अवधारणा को साकार रूप देने के साथ साहित्य से जनमानस को जोड़ने का लक्ष्य लेकर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री मिश्र ने बताया कि यात्रा में साहित्य प्रेमी, बौद्धिक व संत समाज को जोड़ने के उद्देश्य से गोण्डा व लखनऊ में आयोजित परिसंवाद में शून्य व लोक मंगल विषय पर चर्चा किया जाएगा।

सिटी अकादमी के कला विभाग में सुलेख प्रतियोगिता आयोजित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के अनुक्रम में सिटी एकेडमी कला विभाग चिनहट, लखनऊ के छात्र–छात्राओ के द्वारा सुलेख

प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। उक्त जानकारी शिक्षिका अनीता गौतम ने दी।

रोडवेज कर्मचारियों को मिलेगी साइबर सिक्योरिटी की खास ट्रेनिंग

संवाददाता

लखनऊ। राज्य सड़क परिवहन निगम साइबर क्राइम के मद्देनजर अब अलर्ट मोड में है। निगम के एमडी मासूम अली सरवर के दिशा निर्देश न में कल से दो दिनी कार्यशाला शुरू हो रही है जिसमे रोडवेज कर्मियों को साइबर क्राइम से बचने के गुर सिखाए जायेंगे। परिवहन निगम जागा है गच्चा खाने के बाद, लेकिन देर से ही सही नए एमडी एक्शन में हैं। उनके मुताबिक रोडवेज के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बाद प्रशिक्षण कर्मचारी साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होगे। परिवहन निगम के कर्मचारियों को साइबर क्राइम से बचने के तरीके मालूम होंगे। इससे उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकेगा।तेजी से बढ़ते साइबर हमले और साइबर फ्रॉड को लेकर उत्तर प्रदेश राज सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों को भी हाईटेक बनाएगा।कुछ माह पहले ही यूपीएसआरटीसी पर साइबर अटैक हुआ था जिससे निगम को काफी नुकसान हुआ था।

डाटा हैक कर लिया गया था। बताया गया था कि यह साइबर हमला रूस से हुआ है सरकारी संस्थाओं में कॉम्प्रीहेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के जरिए साइबर सिक्योरिटी के स्तर का निर्धारण और उसे सही दिशा देने के लिए सरकारी व निजी संस्थाएं हैं यूपीएसआरटीसी ने सकारात्मक शुरुआत की है। बस टिकटिंग प्रणाली को हैकर्स और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों के लिए दो दिनी हाइब्रिड मोड आधारित साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। 21 से 22 सितंबर के बीच यूपीएसआरटीसी मुख्यालय में इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा।

धूमधाम से मनाया गया विज्ञान नगरी का 34वाँ स्थापना दिवस-हुआ प्रतियोगिताओं का आयोजन

-पुरस्कार वितरण से संपन्न हुयी आंचलिक विज्ञान नगरी की 34वीं वर्षगांठ-

-बच्चों में वैज्ञानिकता को बढ़ावा देकर देश सेवा कर रही है विज्ञान नगरी-एम0 अंसारी

-विज्ञान नगरी की गैलरियों के वैज्ञानिक प्रदर्श है मुख्य आकर्षण के केन्द्र-

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। राजधानी के अलीगंज स्थित आंचलिक विज्ञान नगरी में प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण के साथ 34वीं वर्षगांठ संपन्न हुयी। दिनांक सात सितंबर से इक्कीस सितम्बर तक चले आयोजन में राजधानी के स्कूली बच्चों के लिये अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब एक हजार से अधिक स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। विजेजा बच्चों को पुरस्कार, प्रमाण–पत्र व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विज्ञान नगरी के परियोजना समन्वयक एम0 असांरी

ने कहा कि विज्ञान नगरी अपने वैज्ञानिक क्रिया–कलापों एव विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से पिछले 34 वर्षों से बच्चों मे वैज्ञानिक अभिरूचि उत्पन्न कर रहा है। दूर–दराज के इलाकों के लिये विज्ञान नगरी में दो मोबाइल बसें है जो समय–समय पर गांवों और कस्बों में जाकर बच्चों में वैज्ञानिक रूचि उत्पन्न कर रही है। पुरस्कार वितरण के अवसर पर विज्ञान नगरी के शिक्षा अधिकारी राम कुमार ने बताया कि 34वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्विज व पोस्टर प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ–साथ आम जन–मानस के लिये टेलीस्कोप के माध्यम से आकाश दर्शन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। साथ ही लोगों ने 3–डी शो, साइमैक्स व यहां की गैलरी में वैज्ञानिक प्रदर्शों को भी देखा। उन्होनें बताया कि 7 सितम्बर 1989 में आंचलिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना हुयी थी तथा 21 सितंबर को इसका उच्चीकरण कर इसे आंचलिक विज्ञान नगरी में बदल दिया गया था।

स्कूली बच्चों को सीएफओ ने दिया आग से बचाव हेतु दिये सुरक्षात्मक टिप्स

अयोध्या। गुरुवार को टाइनी टाट्स ग्रुप ऑफ स्कूल के बच्चे व अध्यापकों ने आग से बचाव तथा फायर स्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये फायर स्टेशन पुलिस लाइन का भ्रमण किया। इस मौके पर जिसमें सीएफओ महेन्द्र प्रताप सिंह व उनके टीम में शामिल अग्निशमन कर्मियों ने वहां पर आये बच्चों व अध्यापकों को आग से बचाव संबंधी जानकारी दिया। इस दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने उनको फायर स्टेशन की भूमिका,अग्निशमन उपकरण व फायर टेण्डर के बारे में विस्तार रुप से जानकारी प्रदान किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने अध्यापकों व बच्चों को आग से बचाव संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि जब भी किसी जगह सिलेंडर में आग लगे तो उसके ऊपर जूट से निर्मित बोरे फेके।जब कोई भी व्यक्ति आग

की चपेट में आ जाए तो घबरा कर उसके ऊपर पानी न फेके।बल्कि उसे कंबल से ढके।आग की चपेट में आए व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए क्योंकि आग आक्सीजन से आग और फैलता है।उन्होंने अग्निशमन संबंधी और महत्वपूर्ण जानकारियां बच्चों व अध्यापकों को दिया।इस मौके पर टाइनी टाट्स की अध्यापिका सिंदूरी रस्तोगी,भावना,आदिति निगम व अग्निशमन विभाग के कर्मियों में फायर सर्विस चालक राम प्रसाद पाण्डेय,प्रदीप कुमार,हृदयनाथ विश्वकर्मा, फायरमैन सुनील तिवारी, अवधेश पाण्डेय, सुनील कुमार, अमन शुक्ला व अन्य मौजूद रहे।

राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन करते हुए भारत रक्षा दल ने अपना 27 वां स्थापना दिवस प्रेस क्लब हजरतगंज में मनाया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन करते हुए भारत रक्षा दल ने अपना 27 वां स्थापना दिवस प्रेस क्लब हजरतगंज में मनाया ।

इस अवसर पर समारोह में लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल बतौर मुख्य अतिथि मंचासीन रही है। सभी संस्थापक सदस्य व संस्थापक मंडल पदाधिकारीगणों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए संगठन को राष्ट्र निर्माण में पहली पंक्ति में खड़ा करने का आहवान किया गया। सभी संस्थापको को माल्यापर्ण कर मोमेंटो भेट किया गया । अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष घोष ने किया तथा संचालन केंद्रीय प्रमुख महासचिव के० के० राय (एडवोकेट) ने किया। अतिथि को मोमेंटो व अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया । आयोजन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह यादव ने कहा कि भारतवर्ष के नवयुवक को बढ़ चढ़कर अपना योगदान देना होगा । स्थापना समारोह को मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव ओ० पी० आजाद, प्रदेश कोषाध्यक्ष पृथ्वीपाल, दिनेश लोधी व प्रशांत सिंह ने समवेत स्वर में दल को प्रहरी के रूप में कार्य करने का आहवान किया। उक्त आयोजन में राजेंद्र खना, अलोक पाल, अजय कौरा, मनिंदर सिंह बबली प्रदीप सिंह यादव, विनय चौबे, सत्यम तिवारी, आनंद श्रीवास्तव, राहुल सिंह, रामकांत यादव, देवेन्द्र शर्मा, दिनेश शर्मा, शशि दुबे, आशीष यादव, अरविन्द शुक्ला, महेश सिंह, धर्मेन्द्र लोधी, सुरेन्द्र सोनकर, सैफ खान, सतीश यादव, लवलेश पाण्डेय, आराधना पाल, कमल श्रीवास्तव, राजेंद्र यादव, अभिषेक कश्यप, शांति, धीरेन्द्र तिवारी, मुन्ना सिंह, सुरेश निषाद आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन

संवाददाता

बस्ती। बस्ती में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन पदाधिकारियों, सदस्यों ने जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में 23 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। धरने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाल करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कैशलेश चिकित्सा में प्रत्येक बीमारी का इलाज, ओपीडी से इलाज में कैशलेश चिकित्सा लागू करने, सेवा निवृत्त पेंशनरों को 65, 70, 75 वर्ष पर क्रमशः 5, 10, 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किए जाने, राशिकृत अंश की वापसी, कोराना काल में फ्रीज डीए का भुगतान, रोडवेज की बसों में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने, पेंशन में आयकर की कटौती न करने, वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की भांति रेल किराए में छूट दिए जाने आदि की मांग शामिल है। मण्डलीय सचिव अवधेश कुमार यादव ने कहा कि मांगों को लेकर 3 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला मंत्री उदय प्रताप पाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामनाथ, उपाध्यक्ष प्रेम शंकर लाल श्रीवास्तव, चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, ई. रामचन्द्र शुक्ल, विशुनचन्द श्रीवास्तव, श्रीनाथ मिश्र, ई. राधेश्याम त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष छोटेलाल यादव, विशुनचन्द श्रीवास्तव, राम मिलन चौधरी, ई. सदानन्द, चन्द्रभान चौधरी, योगेन्द्रनाथ यादव, उदयराज वर्मा, जग प्रसाद त्रिपाठी, अंसार अहमद, रहमतुल्लाह, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, मंगलदेव शुक्ल, राम बिहारी तिवारी, रत्नेश कुमार मिश्र आदि शामिल रहे।

सघन मिशन इन्द्रधनुष सहित अन्य अभियान की सफलता को लेकर बैठक सम्पन्न

अयोध्या। डीएमसी यूनिसेफ अयोध्या हवलदार सिंह यादव के मार्गदर्शन मे गुरुवार को कंपोजिट विद्यालय भदरसा मे मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना विभाग सावित्री पाण्डेय की अध्यक्षता मे आगामी सघन मिशन इंद्र धनुष (टीकाकरण)अभियान 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक और आगामी संचारी / दस्तक अभियान 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचारी और 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनसमुदाय और महिलाओं के साथ बैठक किया।जिसमे ब्लॉक मोबिलाइजेसन कोआडिनेटर यूनिसेफ धीरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि इसमें जीरो से पांच साल के ऐसे बच्चे को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीकाकरण होना है।जैसे टी. बी. खसरा रुबेला. पोलियो. पीलिया. गला घोंटू. काली खांसी. टेटनस. निमोनिया. दिमागी बुखार. दस्त प्रबंधन. जिनका पूर्व मे टीका छूट गया है. साथ ही साथ गर्भवती महिलाओ को टेटनस के टीके लगेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि आने वाला अक्टूबर माह बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपाय करने होंगे।पानी नहीं इकट्ठा होने देना है। मच्छर दानी का उपयोग करें। शून्य से पांच साल के बच्चों को जापानी इनसेफलाइटिस का टीकाकरण करवाएं।किसी भी तरह के बुखार होने पर नजदीकी अस्पताल मे खून की जाँच करवाएं।ताजा भोजन करें।साफ पानी को पिए।नाली की सफाई रखें।झाड़ी की कटाई करें।धीरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने संचारी दस्तक अभियान से संबंधित जेवर. नॉएडा का अनुभव साझा किया।इसके साथ ही मुख्य सेविका सावित्री पाण्डेय ने बताया की बच्चों के पोषण पर खास ख्याल रखना है।और गर्भवती महिलाएं पता चलते ही पंजीकरण करवाएं और टेटनस के टीके लगवाएं। इस अवसर पर ब्लॉक रिस्पॉन्स टीम के सदस्य बिपिन गुप्ता,आशा ललिता, आंगनवाड़ी बेबी तबस्सुम उपस्थित रहीं।

शांति मार्च का नगर में पुष्प वर्षा के साथ हुआ भव्य स्वागत

विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पालिका अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर 2023 को नगर के मुख्य मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति वक्ता एवं विश्व शांति दूत तथा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना चुकी हियर योरसेल्फ, स्वयं की आवाज के लेखक प्रेम रावत के अनुयायियों द्वारा नगर के मुख्य मार्गों पर 'शांति मार्च' निकाल कर शांति का संदेश नगर वासियों को दिया गया। नगर के शाहिद उद्यान कंपनी बाग से निकल गई इस शांति मार्च को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती पीके वर्मा तेज तर्रार विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर ख्याति लब्द समाज सेवी अरुणेश बाजपेई और डाक अधीक्षक आरके श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान रफी अहमद इंटर कॉलेज के बच्चों द्वारा स्काउट बैंड बजाकर शांति मार्च में चार चांद लगा दिए ।

शांति मार्च ठीक 9रू00 बजे कंपनी बाग से रवाना हुआ शांति मार्च पर नुमाइश चौराहे पर जितेंद्रा ऑटो पार्ट्स के कर्मचारियों द्वारा पुष्प वर्षा की गई इसके बाद वेणी माधव इंटर कॉलेज के सामने समाजसेवी महेश गुप्ता डब्लू, पूर्व सभासद राजीव गुप्ता, सभासद अजय शर्मा दीपू, सभासद संतोष सैनी ने पानी की बोतल बांट कर पुष्प वर्षा की। बड़ा चौराहे पर कुणाल ज्वेलर्स ने पुष्प वर्षा की वहीं बड़े चौराहे पर अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेवक गुप्ता ने पुष्प वर्षा कर शांति मार्च का स्वागत किया सिनेमा चौराहे पर रामशरण गुप्ता और गुड्डू पान वालों ने पुष्प वर्षा कर शांति मार्च का स्वागत किया डॉक्टर एपी सिंह के सामने दलेल नगर गांव के प्रधान महेश गुप्ता ने अपने साथियों के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया पत्रकार संगठन से जुड़े पत्रकारों के अध्यक्ष रितेश मिश्रा और दिवाकर मिश्रा ने पुष्प वर्षा कर शांति मार्च का स्वागत किया लखनऊ चुंगी पर एसबीआई लाइफ के शाखा प्रबंधक आशीष निगम ने पुष्प बरसा कर शांति मार्च का स्वागत करते हुए सराहन की लखनऊ चुंगी के आगे पेट्रोल पंप के पास कुसुम कुमारी सुनीता आदि ने उसे वर्षा कर स्वागत किया जगह–जगह पर शांति मार्च का भव्य स्वागत किया गया नगर में पहली बार विश्व शांति दिवस पर शांति मार्च निकल गया तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति वक्त प्रेम रावत जी के कोटेशनो के स्लोगन की पट्टीकाएं है और बैनर हाथों में दिखाई पड़ रहे थे इस शांति मार्च में महिलाओं ने बढ़–चढ़कर भागीदारी की करीब 2 किलोमीटर लंबे इस शांति मार्च के दौरान लोग बहुत उत्साहित दिखे। शांति मार्च में षजिस शांति की तुम्हें तलाश है वह तुम्हारे अंदर हैष् घट घट मोरा साइयां सूनी सेज न कोई बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होईष् मृग नाभी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहि ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाहि, ष्आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट हवा लगी संसार की हो गए वारह वाट, से लिखी हुई पटिटकाएं और बैनर लिए हुए थे।

शांति मार्च को हरी झंडी दिखाने आए अतिथियों को स्वयं की आवाज और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया इस दौरान अतिथियों के बैच लगाकर तिलक भी लगाया गया अतिथियों ने कहा कि इस शांति मार्ग को हरी झंडी दिखाकर वह अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं

शांति मार्च का समापन एक लान में विश्व शांति दूत प्रेम रावत के शांति संदेश का प्रसारण डेलाइट पर किया गया जिसे सुनकर उनके अनुयाई झूम उठे।

175 वाहनों का फिटनेस फेल होने पर पंजीयन किया गया निरस्त

रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव

हरदोई –वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया है कि जनपद हरदोई में स्कूलोंष् महाविद्यालयों में संचालित 753 वाहनों में 175 वाहन फिटनेस फेल है फिटनेस कराने हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस देने के पश्चात् भी उक्त 175 फिटनेस फेल वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों का फिटनेस नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 52 में निहित प्राविधानानुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है। ऐसी दशा में यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा और यान मोटरयान अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमावलियों के प्राविधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण विफल होने की स्थिति पर उपरोक्त वाहन का 21 सितम्बर 2023 से 06 माह के लिए पंजीयन निलम्बित किया जाता है। साथ ही सम्बन्धित वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने वाहन की पंजीयन पुस्तिकाष् अन्य प्रपत्र तत्काल प्रभाव से कार्यालय में जमा करें।

फुटबाल प्रतिस्पर्धा में आर आर इण्टर कालेज विजेता बना

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)। आज जनपदीय विद्यालयीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आर आर इ कालेज हरदोई में बालक सीनियर वर्ग प्रतियोगिता आर आर इ का तथा एस डी कालेज के बीच हुई।आर आर प्रधानाचार्य के पी सिंह एस डी कालेज के प्रवक्ता राजबीर सिंह से खिलाड़ियों से परिचय कराया। दूसरा मैच सब जूं वर्ग का आर आर तथा कमपोजिट वि दीनानगर कछौना के बीच हुआ दोनों ही मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए आर आर इण्टर कालेज विजेता रहा। एस डी कालेज तथा कमपोजिट वि दीनानगर उपविजेता रहे।अनुकल राजपूत नीलेश लविश अनुराग अंशुमान नमनसिह अक्षयकुमार अहम आयुशपाल सत्येन्द्र कुमार आयुष कुमार अनुराग सिंह अभय सोनकर अनस शौर्य देवेश अर्पित संकर्षण रीतेश मोहित सचिन आदि छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों ही मैचों में निर्णायक अश्विनी यादव रहे। लाइनमैन की भूमिका हर्षित गुप्ता इनोश मानी सिद्धांत सिंह नमनसिह ने निभाई । कालेज के प्रधानाचार्य कौशलेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता राजबीर सिंह राजकुमार मिश्रा सर्वेश शुक्ल ने सभी प्रतिभागियों को मेंडल पहनाकर सम्मानित किया इस अवसर पर प्रदीप श्रवण कुमार मिश्र आदर्श कुमार आदि उपस्थित रहे अन्त में प्रधानाचार्य ने सभी खिलाड़ियों से कहा मैंच एकजुट होकर सही पास देकर खेलना चाहिए उन्होंने फुटबॉल के बारे में मेराडोना तथा पेले के बारे में बताया। प्रतियोगिता क्रीड़ा प्रभारी श्याम नारायण त्रिवेदी की देखरेख में सम्पन्न हुई।

कस्बे में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश महोत्सव

रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव

पाली– (हरदोई) कस्बे में इस समय गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश महोत्सव देखने के लिए नगर व क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नगर के मोहल्ला खारा कुआं में गणेश महोत्सव दुर्गा मंदिर पर चल रहा है मंदिर कमेटी की तरफ से दूर दराज के जिले से कलाकारों को बुलाया गया है।

वहीं कलाकारों द्वारा सुंदर झांकियां व भजन का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। शाम होते ही काफी संख्या में लोग महोत्सव में पहुंचकर आनंद ले रहे हैं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष गोपाल बाजपेयी ने बताया नगर की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से देख रही है इसके बावजूद उन्होंने मंदिर कमेटी की तरफ से अपनी टीम को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है जिससे आने–जाने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष की भाति इस वर्ष गणेश महोत्सव की भव्यता देने के लिए मंदिर कमेटी ने पूरी तरीके से कोशिश की है वहीं नगर के बुजुर्गों की माने इस वर्ष मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने गणेश महोत्सव की भव्यता काफी दी है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार शुक्ला ने कहा है कि गणेश महोत्सव की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जायेगी।

हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में आज भी हड़ताल पर रहे वकील

संवाददाता

लखनऊ। हापुड़ में वकीलों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ और हापुड़ में वकील बुधवार को भी हड़ताल पर रहे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने लखनऊ में राज्य के मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बाद 14 सितंबर को हड़ताल वापस ले ली थी। हालांकि, लखनऊ बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया। लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप नारायण ने बताया कि लखनऊ बार एसोसिएशन की आम सभा की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें वकीलों ने 21 सितंबर तक न्यायिक कार्य से दूर रहने और उस दिन भविष्य की कार्रवाई पर फैसला करने का फैसला किया। महासचिव ने कहा कि हापुड़ लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई और इससे वकीलों में आक्रोश है। हम हापुड़ के वकीलों के साथ हैं। उनकी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। यूपी बार काउंसिल द्वारा हड़ताल वापस लेने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 15 सितंबर को हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक सहित तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक (हापुड़) अभिषेक वर्मा ने बताया था कि सरकार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मुकेश चंद्र वर्मा, क्षेत्राधिकारी (शहर) अशोक कुमार सिसोदिया और हापुड़ नगर के थाना प्रभारी सतेंद्र प्रकाश सिंह को जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। यूपी सरकार ने राज्य में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। विधि विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अपर महानिदेशक (अभियोजन) इसके सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। बार काउंसिल से अपने सदस्य का नाम देने का अनुरोध किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशों से राज्य विधि आयोग को आगे की कार्रवाई पर विचार के लिए अवगत कराएगी।

पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर मीडिया को वास्तविक आजादी देने की मांग

संवाददाता

लखनऊ। देश के सभी प्रांतों में पत्रकारों को एक समान सुविधाएं प्रदान की जायें तथा देश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर देश के सभी राज्यों में मीडिया को वास्तविक आजादी प्रदान की जाय। यह बात मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार धनराज महेश्वरी ने कही। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सर्व सम्मति से गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी, उपाध्यक्ष केशव कुमार पाण्डेय व श्रीमती पूनम माटिया, महासचिव डॉ. अनिल कटियार, सचिव मोनिका महाजन, संगठन सचिव राजेश त्रिवेदी, संगठन प्रभारी रमेश शंकर पाण्डेय, कोषाध्यक्ष अमृता पाण्डेय, प्रवक्ता विकास त्रिवेदी, सदस्य रजनीश पाण्डेय, जयप्रकाश तिवारी, धनञ्जय कुमार, गायत्री शुक्ला, रवींद्र कुमार शर्मा घोषित किये गए। अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति में आठ राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किये गए हैं। संगठन विस्तार की स्थिति में अन्य राज्यों के पत्रकारों को भी केंद्रीय इकाई में स्थान दिया जायेगा।

एस0 के0 डी0 एकेडमी डिग्री कालेज द्वारा 2020 बैच के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एस0 के0 डी0 एकेडमी डिग्री कालेज वृन्दावन योजना ने आज अपने 2020 बैच के छात्रों के लिए एक गर्म स्वागत और विदाई समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन व वंदना से हुआ। तत्पश्चात् संस्था की सह निदेशक श्रीमती कुसुम बत्रा व डॉ0 नवीन कुलश्रेष्ठ का स्वागत किया गया। उन्होंने छात्रों को उनके उत्कृष्ट पढ़ाई की प्रशंसा और शुभकामनाएं दीं।इस विदाई समारोह के दौरान एसकेडी एकेडमी डिग्री कालेज के प्रमुख शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट अध्ययन के लिए प्रशंसा और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। छात्रों ने इस समारोह को यादगार बनाने के लिए विभिन्न कला प्रस्तुत की, जिनमें गीत–नृत्य और कविता पाठ शामिल थे। एसकेडी एकेडमी डिग्री कॉलेज के प्राध्यापकों ने बताया कि छात्रों के साथ काम करने का यह समय उनके लिए उद्भुत था और उनकी प्रगति पर गर्व है। समारोह के अंत में संस्था के निदेशक श्री मनीष सिंह ने छात्रों को विदाई के इस पल पर शुभकामनाएं दीं कि वे अपने भविष्य की दिशा में सफल हों और अपने सपनो को पूरा करें। एसकेडी एकेडमी डिग्री कालेज 2014 में प्रारम्भ हुआ एवं इसका उद्देश्य छात्रों को उत्तम शिक्षा एवं नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसी क्रम में हमारे कई विद्यार्थियों ने सरकारी विभागों व शीर्ष के विद्यालयों में प्रवेश लिया है। एसकेडी एकेडमी डिग्री कालेज इस समारोह का आयोजन करने लिए सभी छात्रों को धन्यवाद देता हैव उनके भविष्य के लिए आशीर्वाद देता है।

1008 कलशों से भगवान शांतिनाथ एवं महावीर स्वामी का अभिषेक

संवाददाता

लखनऊ। दशलक्षण पर्व के दूसरे दिन बुधवार को इंदिरानगर जैन मंदिर मे चल रहे व्याख्यान मे ब्रह्मचारी श्रीपाल ने बताया कि मान कषाय हलाहल जहर के समान है एवं अहंकार करना नरक मे जाने का कारण हो सकता है। उत्तम मार्दव धर्म हमें कोमलता सिखाता है एवं इसको धारण करने वाल व्यक्ति सदेव सुख पाता है ।

हिन्दी सांध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित ।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI संन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।